



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 254]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 1999/कार्तिक 21, 1921

No. 254]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 1999/KARTIKA 21, 1921

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1999

विषय :— परिधान एवं निटवियर-निर्यात हकदारी (कोटा) नीति (2000-2004) उन देशों के संबंध में जहां ऐसे निर्यात वस्त्र एवं क्लोदिंग पर करार के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधों के अधीन हैं।

1. भूमिका :

सं. 1/128/99 निर्यात-1.—यू एस ए, कनाडा एवं यूरोपीय संघ को सिले सिलाये परिधान एवं निटवियर के निर्यात के संबंध में निर्यात एवं आयात नीति (1997-2002) के अंतर्गत प्रकाशित निर्यात एवं आयात के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के परिशिष्ट 1, अनुसूची 2 की मद सं. 8 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, वर्ष 2000 से 2004 के लिए हकदारी के आबंटन के लिए नीति (इसके बाद आबंटन नीति के रूप में उल्लिखित) इसके बाद में ब्यौरे होंगे।

2. संचालन :

§ 1§ जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली निर्यात हकदारियों का आबंटन करेगा। इस आबंटन नीति के अंतर्गत आने वाले सिले सिलाए परिधानों तथा निटवियर के सभी निर्यातों के लिए आवश्यक प्रमाणीकरण भी महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा।

§ 2§ इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद का अभिप्राय उनसे तथा ऐसे अन्य अधिकारियों से होगा जिन्हें वो आवश्यक उत्तरदायित्व अंशतः तथा पूर्णतः स्पष्टतया अथवा अन्यथा प्रत्यायोजित करें।

§ 3§ महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद दारा लागू किसी भी प्रत्यायोजन के होते हुए भी इस आबंटन नीति के क्रियान्वयन के लिए वे वस्त्र मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होंगे ।

§ 4§ वस्त्र मंत्रालय इस अधिसूचना के उपबंधों में से किसी भी उपबंध को निर्यात संबंध में अंतिम प्राधिकारी होगा । वस्त्र मंत्रालय प्रशासन अभिकरणों, उनके कार्यों तथा निर्यात संबंध में समय-समय पर ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी कर सकता है जैसा वह उचित समझे और वह ऐसे प्राधिकारियों को कार्यों तथा दायित्वों को अंशतः अथवा पूर्णतः पुनर्आबंटित कर सकता है, जैसा कि उचित समझे ।

§ 5§ निर्यात हकदारी समय-समय पर लागू निर्यात-आयात नीति के अनुसार पंजीकृत करने वाली सक्षम प्राधिकरण के पास केवल पंजीकृत निर्यातकों को आबंटित किया जाएगा ।

3. आधार वर्ष :

आबंटन वर्ष के लिए वाक्यांश "आधार वर्ष" जहां कहीं भी इस अधिसूचना में आता हो, उसका अभिप्राय आबंटन वर्ष के तत्काल पूर्व का वार्षिक वर्ष होगा । उदाहरण के लिए, आबंटन वर्ष 2000 के लिए, आधार वर्ष 1998 होगा ।

4. आबंटन की प्रणाली:

§ 1§ प्रत्येक आबंटन वर्ष में निर्यात के लिए मात्राओं को निम्नलिखित प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाये गए दरों पर आबंटित किया जाएगा ;

<u>आबंटन प्रणाली</u>	<u>वार्षिक स्तर का प्रतिशत</u>
विगत निष्पादन हकदारी § पीपीडू § प्रणाली	70%
§ जिसमें एच वी डू §	§ 5%
नया निवेशक हकदारी § एन आई डू § प्रणाली	15%
नया कोटा हकदारी § एन व्यू डू § प्रणाली	5%
पहले आओ पहले पाओ § एफसीएफएस § हकदारी प्रणाली	10%

§ 2§ अभ्यर्पित, लोचता अथवा अन्य प्रकार के कारण समय-समय पर उपलब्ध मात्राओं को भी पहले आओ पहले पाओ § एफसीएफएस § प्रणाली के अंतर्गत आबंटित किया जाएगा ।

§ 3§ वस्त्र मंत्रालय के पास उपरोक्त से भिन्न हकदारियों को आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा यदि यह उस प्रकार से मात्रा पद्धति में परिवर्तनों तथा/अथवा अन्य उचित कारणों के मद्देनजर वांछित समझा जाए । मंत्रालय निटवियर, ऊनी उत्पादों, बच्चों के कपड़े अथवा अन्य किसी देश/श्रेणी के लिए मात्रा भी सुरक्षित रख सकता है । इस प्रकार की सुरक्षित मात्रा उन उत्पादों के लिए एफ सी एफ एस प्रणाली में कार्य करेगा जिसके लिए 30 सितंबर तक उन्हें आरक्षित रखा गया है तथा 1 अक्टूबर की स्थिति अनुसार आरक्षित मात्राओं से अनाबंटित शेष को ऐसे देशों/श्रेणियों के लिए बिना किसी आरक्षण के एफ सी एफ एस प्रणाली में प्रयोग के लिए उपलब्ध किया जाएगा ।

5. उच्च मूल्य हकदारी § एच वी ई § प्रणाली सहित विगत निष्पादन
हकदारी § पीपीई § प्रणाली

आवेदन पत्र तथा परिकलन:

§ 1 § इस प्रणाली में आबंटन के लिए उद्दिष्ट मात्राओं को 1 जनवरी को उपलब्ध कराया जाएगा तथा इस उद्देश्य के लिए पूर्व वर्ष के दौरान कोटा संचालन प्राधिकरण द्वारा आवेदकों को आमंत्रित किया जाएगा ।

§ 2 § महानिदेशक ए वी सी पीपीई की संगणना करेंगे ।

§ 3 § उपलब्ध स्तरों को आवेदकों द्वारा प्रत्येक देश/श्रेणी में आधार वर्ष के दौरान निर्यात के मूल्य पर समानुपात में आबंटित किया जाएगा । तथापि, आबंटन के आधार वर्ष के दौरान देश/श्रेणी में भारत के औसत वार्षिक निर्यात निष्पादन तक सीमित रहेगा ।

परिकलन-एच.वी.ई

जिन निर्यातकों ने आधार वर्ष के दौरान किसी देश-श्रेणी विशेष में विगत निर्यात हकदारी के लिए आवेदन किया है उन सभी निर्यातकों की औसत इकाई मूल्य वसूली का निर्धारण किया जाएगा तथा और ऐसे निर्यातक जिन्होंने औसत इकाई मूल्य से उच्च इकाई मूल्य वसूल किया है, उन्हें उस देश-श्रेणी के अलग-अलग निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात से गुणा करके एक देश-श्रेणी में वसूले गए इकाई मूल्य तथा निर्यातक द्वारा वसूले गए औसत इकाई मूल्य के अंतर के आधार पर 5 प्रतिशत आरक्षित पूल § एच वी ई § में से अतिरिक्त मात्राएं आबंटित की जाएंगी । अलग-अलग निर्यातकों की एचवीई को उनकी पी पी ई में जोड़ा जाएगा तथा यह पी पी ई पर लागू होने वाली सभी शर्तों के अध्याधीन होगा ।

आबंटन, उपयोगिता तथा परिवर्तनीयता:

§ 5 § आबंटन दो भागों में होगा प्रत्येक आबंटन का 50% होगा । प्रथम भाग 31 मई तक आबंटन की तिथि से वैध होगा तथा दूसरा भाग 30 सितंबर तक वैध होगा ।

§ 6 § 31 मई तक वैध आबंटन के मामले में, परिवर्तनों को अंतिम तिथि तक अनुमति दी जा सकती है परंतु मूल कोटा धारक अथवा परिवर्तनकर्ता को हकदारी के मामले में 31 मई तक लदान का प्रमाणन/पुष्टि प्राप्त होगी । ऐसा प्रमाणन/पुष्टि कोटा वर्ष के 20 जून तक लदान के लिए वैध होगा । अनप्रयुक्त कोटा § गैर प्रमाणित अथवा गैर लदान § समाप्त हो जाएगा ।

§ 7 § 30 सितंबर तक वैध आबंटन की स्थिति में, परिवर्तनों को 20 सितंबर तक अनुमति

दी जा सकती है। मूल कोटा चारक अथवा हस्तांतरणकर्ता को नीचे दी गई दरों पर बी जी/इ एम डी के भुगतान पर 31 दिसंबर, तक इस शर्त पर बढ़ाया जा सकता है कि मांगी गई वृद्धि एक विशिष्ट क्रेता के लिए है। महानिदेशक, ए ई पी सी द्वारा अन्य लागू शर्तों को बदले बिना क्रेता का एक बार परिवर्तन करने की अनुमति दे सकता है।

उत्पाद समूह -----	इ एम डी/बी राशि -----
यू एस ए में शाक्स/ग्लोब्स	रु0 2/- प्रति दर्जन जोड़ा
कनाडा में अंडरवियर	रु0 5/- प्रति पीस
कनाडा में समूह-क	रु0 12/- प्रति वर्ग मी0
यू एस ए में समूह-2	रु0 12/- प्रति एस एम ई
यूरोपीय संघ में श्रेणी 4,5 एवं 24	रु0 12/- प्रति नग
अन्य	रु0 20/- प्रति नग

§ 8§ ऐसी समयवृद्धि के लिए हर प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र हकदारी की प्रारंभिक वैधता की समाप्ति से पूर्व अथवा 3 दिन की छूट अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

§ 9§ हस्तांतरित पी पी ई पी पी टी के रूप में जाना जाएगा।

§ 10§ पी पी टी के विरुद्ध लदानों को हस्तांतरणकर्ता द्वारा निर्यातों के रूप में गिना जाएगा।

§ 11§ पी पी टी के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण प्रणाली § 4टीएस§

§ 12§ पी पी ई हस्तांतरण एक ऑनलाइन कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण योजना के माध्यम से विनियमित किया जाएगा जिसमें रूढ़िपूर्ण हस्तांतरणकर्ताओं की पेशकशों को मात्रा तथा पेशकश मूल्यों सहित ए ई पी सी के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाएगा तथा रूढ़िपूर्ण हस्तांतरणकर्ता प्रदर्शित पेशकशों के आधार पर हस्तांतरण के लिए आवेदन करेंगे। पेशकशों एवं अनुरोधों को डी जी, ए ई पी सी द्वारा निर्धारित कार्यघंटों के दौरान प्राप्त किया जाएगा तथा इस प्रकार की प्राप्त सभी पेशकशों एवं अनुरोधों को एक साथ प्रोसेस किया जाएगा। अनुरोधों को केवल उपलब्ध पेशकशों के विरुद्ध किया जाएगा। तथापि, अगर किसी विशेष देश/श्रेणी के लिए कोई पेशकश प्रदर्शन पर नहीं है, अनुरोध किए जाने के लिए मात्राओं पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तथा अनुरोध कीमत दर्शायी जानी है।

§ 13§ महानिदेशक, ए ई पी सी ट्रेड को उचित सूचना देने एवं वस्त्र मंत्रालय को सूचित

करने के पश्चात इ टी एस के सुगम एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो भी आवश्यक समझा जाए, कदम उठा सकता है ।

6. नया निवेशक हकदारी §एन आई इ§

आवेदन एवं संगणना

§1§ एन आई ई प्रणाली के अंतर्गत आबंटन केवल पंजीकृत निर्यातकों जो विनिर्माता-निर्यातकों के रूप में तथा जिन्होंने मौजूदा एकक अथवा एक नये एकक में नयी मशीनरी में 50 लाख रु की न्यूनतम राशि का निवेश किया है, को किया जाएगा । ऐसी मशीनरी इस समय लागू प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना की पात्रता के मानदंडों को पूरा करेंगी ।

§2§ इस प्रणाली के अंतर्गत आबंटन केवल आधुनिकीकृत तथा उन्नत उत्पादन एकक में विनिर्मित सामानों के निर्यात के लिए केवल होगा ।

§3§ आबंटन लदानों के प्रमाणन के समय एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि निर्यात किए जा रहे सामानों का इस प्रकार आधुनिकीकृत/उन्नत उनके उत्पादन एककों में निर्माण किया गया है ।

§4§ एन आई ई के लिए आधार अवधि आधार वर्ष के 1 जनवरी के आरंभ से तथा पूर्व वर्ष के 30 जून की समाप्ति तक की 12 महीनों की कोई लगातार अवधि होगी । इस प्रकार, कोटा वर्ष 2001 के लिए, 1-1-1999 से 30-6-2000 की 18 महीनों की अवधि में से 12 माह लगातार^{आधार} अवधि बनेगी ।

§5§ एन आई ई के लिए आवेदन कोटा संचालन प्राधिकरण द्वारा पूर्व वर्ष के 30 सितंबर तक स्वीकार की जाएगी । इस प्रणाली के अंतर्गत एक आवेदन के साथ कोटा संचालन प्राधिकरण के पक्ष में देय 500/- रु0 का डिमांड ड्राफ्ट जो नई दिल्ली में देय हो, संलग्न किया जाएगा । आवेदन की अन्य शर्तें वस्त्र आयुक्त द्वारा कोटा संचालन प्राधिकरण के परामर्श से तथा वस्त्र मंत्रालय की पूर्वानुमति के बाद निर्धारित किया जाएगा ।

§6§ एन आई इ के अंतर्गत उपलब्ध मात्रा को कोटा संचालन प्राधिकारी द्वारा पात्र आवेदकों की उत्पादन क्षमता के आधार पर वितरित किया जाएगा ।

§7§ प्रत्येक आवेदकों को आबंटन पात्र निवेश के आधार पर सभी पात्र आवेदकों के बीच समानुपातिक तौर पर वितरित किया जाएगा ।

§8§ वर्ष 2000 के दौरान, एन आई इ आबंटन पूर्व वर्षों से संबंधित एन आई ई के अंतर्गत वचनबद्ध देयताओं को पूरा करेगा तथा यदि देयताएं अधिक हैं, उन्हें समानुपातिक आधार पर पूरा किया जाएगा परंतु आगे नहीं ले जाया जाएगा । पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध श्रेणियों

में से उनके विकल्पों को श्रेणीबद्ध करने की अपेक्षा की जाएगी ।

आबंटन, उपयोगिता तथा हस्तांतरणीयता

§9§ एन आई इ को दो भागों में, जो प्रत्येक भाग के आबंटन का 50% होगा, आबंटित किया जाएगा । प्रथम भाग आबंटन की तिथि से 31 मई तक वैध रहेगा तथा द्वितीय भाग 30 सितंबर तक वैध रहेगा ।

§10§ 31 मई तक एन आई ई के वैध रहने की स्थिति में कोटा धारकों को 31 मई तक हकदारी के मामले के संदर्भ में लदान के लिए प्रमाणन प्राप्त करेगा । प्रमाणन कोटा वर्ष के 20 जून तक लदान के लिए वैध रहेगा । अप्रयुक्त कोटे §गैर-प्रमाणीकृत अथवा लदान न किए हुए§ समाप्त हो जाएंगे ।

§11§ एन आई इ के 30 सितंबर तक वैध रहने की स्थिति में, कोटा धारकों को §11§ में उल्लिखित वरों पर बी जी/इ एम डी के भुगतान पर 31 दिसंबर तक इस शर्त के अधीन विस्तार मिल सकता है कि मांगा गया विस्तार एक विशिष्ट क्रेता के लिए है ।

§12§ ऐसे विस्तार के लिए आवेदनों को, हर तरह से पूर्ण, हकदारी की आरंभिक वैधता की समाप्ति के पूर्व अथवा 3 कार्य दिवसों की छूट अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाए ।

§13§ एन आई इ हस्तांतरणीय नहीं होगी ।

7. गैर कोटा निर्यातिक हकदारी §एन क्यू ई§ प्रणाली

आवेदन एवं संगणना

§1§ गैर-कोटा देशों को परिधान तथा कोटा देशों को गैर-कोटा परिधान के निर्यातिक इस प्रणाली के अंतर्गत आबंटन के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि भुगतान मुक्त मुद्रा में प्राप्त होता है तथा निर्यातिक ने आधार वर्ष के दौरान 20 लाख रु0 का न्यूनतम निर्यात निष्पादन किया हो । तथापि, रुस को परिधान के निर्यात को, एन क्यू इ आबंटनों के लिए शामिल नहीं किया जाएगा ।

§2§ इस प्रणाली में आबंटन के लिए उद्दिष्ट मात्राओं को 1 जनवरी को उपलब्ध किया जाएगा तथा इस उद्देश्य से, आवेदनों को पूर्व वर्ष के दौरान कोटा संचालन प्राधिकारी द्वारा आमंत्रित किया जाएगा ।

§3§ "कोटा संचालन प्राधिकारी" एन क्यू इ की संगणना करेगा ।

§ 4§ इस प्रणाली के अंतर्गत हकदारियों को आधार वर्ष के दौरान प्राप्य निर्यातों के मूल्य के आधार पर कोटा संचालन प्राधिकारी द्वारा परिकल्पित एवं आवंटित किया जाएगा। तथापि, परिधानों का निर्यात, जो इस आवंटन नीति के अंतर्गत आता है, गैर-कोटा देशों को संगणना में दोहरा महत्व दिया जाएगा। उपलब्ध स्तरों को व्यक्तिगत आवेदकों के निर्यात के मूल्य के आधार पर समानुपात वितरित किया जाएगा।

§ 5§ एक निर्यातक को आबंटन के लिए इस-देश श्रेणी समन्वय की पसंद की अनुमति दी जाएगी।

उपयोगिता एवं हस्तांतरणीयता

§ 6§ पी पी ई पर लागू सभी शर्तें, एन क्यू ई पर भी आवश्यक परिवर्तन सहित लागू रहेगी।

§ 7§ एन क्यू ई हस्तांतरणीय है। ऐसी हस्तांतरित हकदारियों इसके बाद एन क्यू टी के रूप में उल्लिखित की जाएगी। तथा हस्तांतरण की शर्तें वही रहेगी जो पी पी ई के मामले में है।

§ 8§ पी पी टी को लागू सभी शर्तें एन क्यू टी को आवश्यक परिवर्तन सहित लागू रहेगा।

६- पहले आठों पहले पाठों (एफ सी एफ एस) प्रणाली

रिलीज सूची

§ 1§ एफ सी एफ एस प्रणाली के अंतर्गत हकदारी वर्ष में दो बार खोली जाएगी। एफ सी एफएस के अंतर्गत हकदारी का 50 / 10 जनवरी को तथा दूसरा 50 / 10 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा।

§ 2§ इस प्रणाली के अंतर्गत मात्राओं के अलावा, समर्पण, लोच अथवा अन्यथा, यदि कोई हो, के माध्यम से जो मात्रा उपलब्ध होती है उसको 10 अप्रैल, 10 जुलाई, 10 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। किसी ऐसे रिलीज पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ, विचार करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न श्रेणियों में मात्राओं की उपलब्धता को भी ध्यान में लिया जाएगा। देश श्रेणियों तथा क्षेत्रों जहां रिलीज किए जाते हैं के साथ-साथ इन तिथियों को रिलीज किए जाने वाली मात्राओं को कोटा संचालन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रिलीज करने से पर्याप्त समय पूर्व घोषित किया जाएगा।

§ 3§ वस्त्र मंत्रालय उपरोक्त § 1।1§ में निर्दिष्ट तिथियों को छोड़कर किसी तिथि में एफ सी एफएस में एफ सी एफ एस प्रणाली में आवश्यक पाये जाने पर मात्राओं को रिलीज करने के लिए निर्णय कर सकता है। ऐसे निर्णय की प्राप्ति पर, कोटा संचालन प्राधिकारी ट्रेड को उचित सूचना देने के पश्चात एफ सी एफ एस प्रणाली में ऐसी मात्राओं को जारी करेगा।

आवेदन

§ 4§ मात्राओं को आवेदनों के आधार पर आबंटित किया जाएगा तथा किसी दिन जब उपलब्ध मात्राओं से अधिक की स्वीकृति दी जाती है तो, पात्रता उस तिथि को प्राप्त आवेदनों के बीच एकक मूल्य वसूली के आधार पर तय की जाएगी ।

आबंटन की वैधता

§ 5§ आबंटन, ऐसे आबंटन की तिथि से 75 दिनों तक वैध रहेंगे ।

आबंटन प्रणाली

§ 6§ एफ सी एफ एस प्रणाली के अंतर्गत आबंटन, शामिल मात्रा के एफ.ओ.बी. मूल्य के 5% की दर से इ एम डी/बी जी के अधीन होगा ।

§ 7§ वस्त्र आयुक्त अधिकतम मात्रा निर्धारित कर सकते हैं जिसे आवेदक द्वारा इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक देश-श्रेणी के लिए कोटा संचालन प्राधिकारी से प्रतिदिन परामर्श कर आवेदन किया जा सकता है ।

हस्तांतरणीयता

§ 8§ एफ सी एफ एस आबंटन हस्तांतरणीय नहीं होगा ।

§ 9§ हथकरघा परिधान

कतिपय देशों के लिए हथकरघा परिधान के लिए आरक्षित विशेष मात्राओं को एफ सी एफ एस प्रणाली के अंतर्गत आबंटित किया जाएगा ।

§ 10§ प्रमाणीकरण की वैधता

§ 1§ एफ सी एफ एस आबंटनों के मामले में लदान बिलों पर प्रमाणन की वैधता, यदि अन्य प्रकार से निर्दिष्ट नहीं हो, आबंटन की तिथि से 75 दिन तक होगी ।

§ 2§ पी पी ई/एन आई ई/ पी पी टी/एन क्यू टी की वैधता, लदान बिल की पुष्टि की तिथि से अथवा हकदारी प्रमाण-पत्र की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, 75 दिन तक होगी ।

§ 3§ उपर्युक्त पैरा 8§5§ में निर्दिष्ट किसी बात के बावजूद वस्त्र आयुक्त व्यक्तिगत मामलों में तीन कार्यदिवसों तक वैधता अवधि का विस्तार मंजूर कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि संबंधित निर्यातक अपने नियंत्रण से बाहर स्थितियों के कारण अवधि के भीतर निर्यात नहीं कर सका ।

कम करोबार की मदें

1. कोई मद को कम करोबार के रूप में अधिसूचित किया जाएगा यदि आधार वर्ष के दौरान उपयोगिता उस वर्ष के लिए वार्षिक स्तर का 75% से कम हो। क्षेत्र संचालन प्राधिकरण कम करोबार की मदों की पूर्व वर्ष के अधिकतम 1 दिसंबर तक अधिसूचित करेगी।

2. इस अधिसूचना के किसी प्रावधानों में निहित किसी अन्य बातों के बावजूद कम करोबार की मदों के लिए ई एम डी/बी जी को एफ सी एफ एस प्रणाली के अंतर्गत तदोपक्रम के लिए बोर्ड पर शुल्क मूल्य का 1% की दर से प्रभावित किया जाएगा।

3. उपर्युक्त पैरा 8 § 7 के दृष्टिकोण एफ सी एफ एस प्रणाली के लिए विनिर्दिष्ट मात्रात्मक प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

4. तथापि कोई छूट बिना कोई सूचना के किसी समय वापस ली जा सकती है।

§ 12. पेशगी जमा राशि/बैंक गारंटी/उत्तर दिनांकित चेक प्रस्तुत तथा जव्त करने के बारे में प्रावधान

§ 12. प्रस्तुती

§ 1. पेशगी जमा राशि § 1-एम-डी सामान्यतः डिपॉजिट स्लॉट, एफ डी आर के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी, जो कि एकपक्षीय रूप से ए ई पी सी अथवा बैंक गारंटी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तथापि, एफ सी एफ एस के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों में कानूनी उत्तर दिनांकित चेक भी पेशगी जमा राशि के रूप में निम्नलिखित निर्धारित शर्तों पर स्वीकार्य होगा।

कानूनी बचनवद्धता § एन यू टी

§ 2. एक्सपोर्ट हाउस/ट्रेडिंग हाउस/स्टार ट्रेडिंग हाउस/सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/विनिर्माता निर्यातक जो इस आबंटन नीति अथवा पूर्व आबंटन नीति § 1997-99 के अंतर्गत को अस्ती आदेश के माध्यम से वंडित नहीं किया गया हो तथा पी पी ड. एन क्यू ड तथा एन आइ ड एन एनियों § पी पी टी, एन क्यू टी सहित के अंतर्गत सभी देश श्रेणियों की एक साथ 25,000 नगों से कम हकदारी नहीं है। निम्नलिखित शर्तों के अधीन हकदारियों के विचार तथा पुनर्विचार के लिए ई एम डी/बी जी की जगह पर एक कानूनी अंडरटेकिंग § एन यू टी प्रस्तुत कर सकते हैं।

§ 3. यदि महानिदेशक ए ई पी सी एक कानूनी अंडरटेकिंग में आने वाली हकदारियों के मामलों में किसी जव्त राशियों के लिए निर्यात हकदारी वितरण नीति के मामलों में दावा उठाता है, संबंधित निर्यातक किन्होंने कानूनी अंडरटेकिंग प्रस्तुत किया है, को बिना किसी हिचकिचाहट अथवा विरोध के ऐसे दावे की तिथि से 90 दिनों के भीतर महानिदेशक, ए ई पी सी द्वारा इस प्रकार वसूली की गई राशि को माफ करना होगा। असफल निर्यातक लदान विलों के किसी प्रमाणन को प्राप्त करने अथवा आवेदन करने, हकदारी का स्थानान्तरण अथवा किसी प्रणाली में ई एम डी/बी जी की वापसी के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि राशि माफ नहीं हो जाती है तथा महानिदेशक, ए ई पी सी निर्यातक के लिए इन सुविधाओं को बहाल करने का निर्णय लेता है।

§ख§ महानिदेशक, ए ई पी सी ऐसे किसी निर्यातक के लिए इ एम डी/ बी जी के स्थान पर पल यू टी प्रस्तुत करने की सुविधा को वापस ले सकता है जो इस सुविधा के लिए अन्य प्रकार से पात्र हैं लेकिन 90 दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जब्त राशि को चुकाने में असफल हो गये हैं ।

§ग§ पल यू टी को जारी/जब्त करने से संबंधित शर्तें वैसी ही होगी जैसा कि इ एम डी/बी जी के अन्य रूपों के लिए लागू हो ।

उत्तर दिनांकित चेक §पी डी सी§

§3§ हकदारियों को बढ़ाने के लिए एफ सी एफ एस के अतिरिक्त अन्य प्रणालियों में उत्तर दिनांकित चेक ई. एम. डी. के रूप में इस शर्त पर स्वीकार्य होंगे कि यदि चेक किसी भी कारण जमा करने के लिए अस्वीकृत कर दिया जाता है तो ऐसे चेकों के आधार पर बढ़ायी गयी मात्राएं से संबंधित निर्यातक की किसी भी प्रकार की भावी हकदारियों के नामे डाल दी जाएगी और उसे तब तक आगे हकदारी आबंटित नहीं की जाएगी जब तक कि जब्त की गई राशि को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लौटाया नहीं जाता ।

§4§ उत्तर दिनांकित चेक पर आबंटन के वर्ष के आद के वर्ष की 1 जून की तारीख अंकित होनी चाहिए और ये उक्त तारीख छः महीनों की अवधि के दौरान प्रस्तुत करने के लिए वैध होनी चाहिए ।

§5§ उत्तर दिनांकित चेकों को जारी/जब्त करने से संबंधित शर्तें वही होंगी जो कि ई. एम. डी./ बैंक गारंटी के अन्य रूपों पर लागू हैं ।

§ख§ रिलीज/जब्त

§6§ अपनी हकदारी के 90% अथवा उससे अधिक का निर्यात करने वाले निर्यातक की ई. एम. डी./बैंक गारंटी/पल यू टी उत्तर दिनांकित चेक को राशि पूरी रिलीज कर दी जाएगी । तथापि, कम कारोबार वाली मदों के बारे में यह प्रतिशत 75% अथवा अधिक होगा ।

§7§ "क्षेत्र संचालन प्राधिकारी" अधिक कारोबार वाली मदों के मामले में 75% अथवा उससे अधिक का लेकिन 90% से कम उपयोग होने तथा कम कारोबार वाली मदों के मामले में 50% अथवा उससे अधिक लेकिन 75% से कम उपयोग होने की स्थिति में ई. एम. डी./बी जी को उपयोग में कमी के समानुपात में जब्त कर लेगा ।

§8§ यदि उपयोग उपर्युक्त से कम रहता है अर्थात् अधिक कारोबार वाली मदों के मामलों में 75% तथा कम कारोबार वाली मदों के मामलों में 50% से कम रहता है तो ई.एम.डी./बी.जी./ उत्तर दिनांकित चेक की पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी ।

§9§ उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उपयोग का परिकल्पन पृथक हकदारियों के आधार पर अथवा प्रत्येक प्रणाली के आधार पर पृथक रूप से अथवा सभी प्रणालियों §एफ सी एफ एस प्रणाली को छोड़कर§ एक साथ मिलाकर निर्यातक के निर्यात निष्पादन के लिए उसके अनुरोध पर किया जाएगा ।

§10§ जब्त करने से पूर्व एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा ।

§11§ क्षेत्र संचालन प्राधिकारी बी.जी./ई.एम.डी./पल यू टी/ उत्तर दिनांकित चेक आदि के

जब्तीकरण के आदेश को पावती सहित पंजीकृत डाक अथवा प्रार्थामिक रूप से स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित करेगा। आदेश को भेजने का साक्ष्य उपर्युक्त विनिश्चित माध्यमों से तथा साथ ही उसकी पावती अथवा आदेश के प्रेषण के अन्य साक्ष्य संबंधित फाइल में रखने चाहिए।

§12§ जब्त की गई राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कोटा संचालन प्राधिकारी निर्यातक को विनिश्चित अवधि के लिए हकदारियाँ प्राप्त करने तथा निर्यात हकदारी वितरण प्रणाली में भाग लेने के लिए अस्थाई रूप से निष्कल सकता है।

§ग§ लोक जमा खाता §पी.डी.ए.।

§13§ सभी जब्त किए गए ई.एम.डी./बी.जी./ उत्तर दिनांकित बैंक सरकार के लोक जमा खाते में उस तरीके से जमा किए जायेंगे जैसा कि सरकार समय-समय पर निर्देश करेगी।

§13§ रोके गए प्रेषणों को जारी करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त :-

§क§ जब आयातक देश द्वारा किसी गैर प्रतिबंधित श्रेणी में किए गए लदान को पुनः वर्गीकृत करके प्रतिबंधित श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है अथवा जब आयातक देश द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी में किए गए लदान को पुनः वर्गीकृत करके अन्य प्रतिबंधित श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में पुनः वर्गीकृत श्रेणी में निहित मात्रा को निर्यातक द्वारा अभ्यर्पित करने के बाद ही पुनः वर्गीकृत श्रेणी में निर्यात प्रमाण पत्र/बीजा जारी किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए निर्यातक एफ सी एफ एस से अन्यत्र प्रणालियों में अपनी हकदारियों में से अथवा अंतरण द्वारा मात्रा प्राप्त करके मात्रा को अभ्यर्पित कर सकता है। यदि मामलों को 20 सितंबर के बाद निपटाया जाना है तो उस स्थिति में हस्तांतरण की अनुमति न होने तथा निर्यातक के पास अपनी हकदारियों में से मात्रा अभ्यर्पित न कर पाने की स्थिति में ऐसे निर्यातक से इस आशय की वचनबद्धता प्राप्त कर ली जाएगी कि वह परवर्ती वर्ष की हकदारी §निजी अथवा हस्तांतरित§ में से 31 जनवरी तक अपेक्षित मात्रा अभ्यर्पित कर देगा। इस प्रकार की वचनबद्धता के साथ मात्रा के एफ ओ बी मूल्य के 50% के बराबर की बैंक गारंटी/ई.एम.डी. प्रस्तुत करनी होगी। एक बार मात्रा अभ्यर्पण हो जाता है बी.जी./ई.एम.डी. रिलीज किया जा सकता है। यदि वचनबद्धता के अनुसार मात्रा अभ्यर्पित नहीं की जाती है तो बैंक गारंटी/ई.एम.डी. जब्त की जा सकती है। ऐसे मामलों में परवर्ती वर्ष के लिए निर्यातक को किसी भी देश-श्रेणी में अपेक्षित मात्रा को अभ्यर्पित करने के बाद ही पी.पी.ई. का आबंटन किया जा सकता है।

§ख§ यदि एफ सी एफ एस प्रणाली में कोटा संचालन प्राधिकारी द्वारा रिलीज की गई मात्राओं में से पुनः वर्गीकृत श्रेणियों में अनावंटित अधिशेष मात्रा उपलब्ध होती है तो ऐसी अधिशेष मात्रा को नामें डालने के बाद ही रोके गए प्रेषण के लिए निर्यात प्रमाण पत्र/बीजा जारी किया जाएगा और निर्यातक को कोई भी मात्रा अभ्यर्पित नहीं करनी पड़ेगी।

§ग§ उपर्युक्त §क§ और §ख§ में उल्लिखित शर्तें ऐसे मामलों पर भी लागू होंगी जहां एफ सी एफ एस प्रणाली के अंतर्गत अथवा 30 सितंबर के बाद प्राप्त की गई बढ़ी हुई अवधि के बाद पी.पी.ई. प्रणाली के अंतर्गत किए गए लदान के लिए क्रेता को बदलना अपेक्षित है तथा ये शर्तें उन मामलों पर भी लागू होंगी जिनमें आयातक देश को बदलना अपेक्षित है।

§घ§ जहां प्रतिबंधित श्रेणी में किए गए निर्यात को उपर्युक्त किसी अन्य प्रतिबंधित श्रेणी पुनः वर्गीकृत किया जाता है तो देश से लदान करने के लिए प्रयुक्त की गई हकदारी निम्नलिखित शर्तों पर निर्यातक को लौटाई जा सकती है।

§14§ सीमा शुल्क विभाग द्वारा क्लीयरेंस

§क§ प्रतिबंधित मदों के अंतर्गत उत्पाद जिनमें वे मदें भी शामिल हैं जो कि संयुक्त राज्य

पोतलदान बन्दरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पोतलदान की अनुमति, महानिदेशक, अपैरल निर्यात संबंधन परिषद द्वारा जारी किए गए निर्यात हकदारी के प्रमाणन के मूल पत्रों तथा अलग अलग माल के लिए जारी किए गए शिपिंग बिलों की जांच करने के बाद दी जाएगी।

§ ख § हथकरघा परिधान

कनाडा में प्रतिबंधित मर्दों के समतुल्य सभी हथकरघा परिधानों के निर्यात के लिए और यू.एस.ए. से संबंधित कुछ प्रतिबंधित श्रेणियों में हथकरघा परिधानों के लिए आरक्षित विशेष मात्राओं के पोतलदान की अनुमति संयोजन प्रमाण पत्र के भाग 2 में वस्त्र संप्रति द्वारा किए गए निरीक्षण पृष्ठांकन के आधार पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा दी जाएगी।

§ ग § "इण्डिया आइटम्स" के अन्तर्गत आने वाले परिधान

"इण्डिया आइटम्स" के संबंध में जो कि भारत की परम्परागत लोक रीति के हस्तशिल्प की वस्त्र उत्पाद मर्दें हैं, उनका ई.यू., संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा को निर्यात करने के उद्देश्य से पोतलदान की अनुमति, विकास आयुक्त §हस्तशिल्प§ के कार्यालय द्वारा जारी किए गए प्रमाणन के आधार पर दी जाएगी।

15. निर्यात प्रमाण पत्र आदि

निर्यात प्रमाण पत्र, मूल स्थान का प्रमाण पत्र तथा बीजा

महानिदेशक, अपैरल निर्यात संबंधन परिषद द्विपक्षीय वस्त्र करार के अन्तर्गत अपेक्षित निम्नलिखित प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

1. ई यू

§ क § प्रतिबंधों के अन्तर्गत समस्त परिधान/निटवियर मर्दों के लिए निर्यात प्रमाण पत्र तथा मूल स्थान का प्रमाण पत्र।

§ ख § समस्त गैर-प्रतिबंधित परिधानों/मर्दों के लिए मूल स्थान का प्रमाण पत्र।

2. कनाडा

परिधानों के लिये निर्यात प्रमाण पत्र जो कि 500 अथवा उससे कम कनैडियन डालर के विधिवत चिह्नित नमूनों को छोड़कर प्रतिबंधों के अधीन है।

3. संयुक्त राज्य अमरीका

250 अथवा उससे कम अमरीकी डालर के मूल्य के विधिवत चिह्नित नमूनों को छोड़ करके समस्त/निटवियर माल के लिए बीजा ।

हथकरघा प्रमाण पत्र

कनाडा को प्रतिबंधित मर्चों के समतुल्य सभी हथकरघा परिधानों के निर्यात के मामलों में हथकरघा परिधानों के रूप में अथवा "इण्डिया आइटम्स" के रूप में निर्यात किया जाता है तो डी.जी., ए. ई. पी.सी., वस्त्र मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात निर्यात बीजा प्रमाण पत्र जारी करेंगे ।

16. ई एम.डी./बी जी/उत्तर दिनांकित चेक को जन्त करने पर अपील

§1§ कोटा संचालन प्राधिकारी द्वारा ई एम डी/बी जी को जन्त करने के आदेश से कथित निर्यातक, प्रथम अपील प्राधिकारी अर्थात् वस्त्र आयुक्त को, कोटा संचालन प्राधिकारी के आदेश के प्रेषण के 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है । यह अपील तीन प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी जिसके साथ वस्त्र आयुक्त के पक्ष में तथा मुंबई में देय 500/- रु० का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा ।

§2§ अपील कर्ता यदि चाहे तो कोटा संचालन प्राधिकारी के आदेश के स्थगन के लिए एक पृथक आवेदन पत्र भी प्रस्तुत कर सकता है ।

§3§ वस्त्र आयुक्त स्थगन के मुद्दे पर यथाशीघ्र निर्णय देंगे ।

§4§ अपील पर भी निर्णय अधिमानतः यथाशीघ्र अर्थात् दो महीनों के भीतर ले लिया जाएगा । यदि अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपयुक्त अवसर दिया जाएगा । अंतिम आदेश गंजीकृत डाक द्वारा "पावती के कार्टु" सहित अथवा अधिमानतः स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया जाएगा तथा उक्त माध्यम से उसके प्रेषण के प्रमाण के साथ उसकी पावती/रसीद सहित अथवा अन्यथा संबंधित फाइल में रखने होंगे ।

§5§ वैध तारीख के बाद दायर की गयी अपील के मामले में वस्त्र आयुक्त प्रथमतः यह निर्णय लेंगे कि क्या ऐसे विलंब को माफ कर दिया जाए अथवा नहीं । वस्त्र आयुक्त ऐसे मामलों में मौखिक आदेश देंगे ।

§6§ उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए वस्त्र आयुक्त से तात्पर्य तथा ऐसे शामिल किए गए अन्य अधिकारी (जो कि निदेशक के पद के नीचे नहीं हों) से है जिसे वस्त्र आयुक्त स्पष्ट रूप से अथवा अन्यथा आवश्यक उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित करते हैं ।

§7§ यदि कोई निर्यातक स्थगन के आवेदन पत्र या अपील के मामले में वस्त्र आयुक्त के निर्णय से

संतुष्ट नहीं होता है तो वह प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश के प्रेषण के 45 दिनों के भीतर ऐसे निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील प्राधिकारी को उस पर निर्णय लेने के लिए अपील दायर कर सकता है ।

§ 8§ इन प्रयोजनों के लिए द्वितीय अपील समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे ।

- | | |
|--|------------|
| § क§ संयुक्त सचिव §निर्यात§, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार | अध्यक्ष |
| § ख§ विधि व न्याय मंत्रालय का एक अधिकारी, भारत सरकार (जो कि भारत सरकार में उप सचिव के पद से नीचे नहीं होगा) | सदस्य |
| § ग§ महानिदेशक, विशेष व्यापार, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार का एक अधिकारी [जो कि भारत सरकार में उप सचिव के पद से नीचे नहीं होगा] | सदस्य |
| § घ§ उप सचिव/निदेशक §निर्यात§, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य सचिव |

इस समिति के अध्यक्ष में इसके अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे ।

§ 9§ द्वितीय अपील प्राधिकारी के समक्ष दायर की जाने वाली कोई भी अपील, उसके सदस्य सचिव को संबोधित होगी जिसकी पाँच प्रतियों के साथ वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में तथा दिल्ली में देय 500 ₹0 का डिपॉजिट शुल्क संलग्न करना होगा ।

§ 10§ यदि अपील कीक विषय वस्तु भी स्थगन से संबंधित होती है तथा वह तात्कालिक प्रवृत्ति की है तो समिति के अध्यक्ष लिखित रूप से कारणों को दर्ज करके, स्थगन की स्वीकृति दे सकते हैं ।

§ 11§ द्वितीय अपील प्राधिकारी भी मामले पर यथा शीघ्र अधिमानतः तीन महीनों के भीतर निर्णय ले लेंगे ।

17. निर्यातकों द्वारा कोट संबंधी अनाचार से निवृत्ति की प्रक्रिया

§ 1§ प्रवर्तन समिति नामक एक समिति की स्थापना की गई है जिसकी संरचना निम्न अनुसार है :-

- | | |
|--|------------|
| 1. वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार | अध्यक्ष |
| 2. महानिदेशक, अपैरल निर्यात संबंधी परिषद | सदस्य |
| 3. विधि तथा न्याय मंत्रालय का एक अधिकारी (जो भारत सरकार में उप सचिव स्तर से नीचे का न हो) | सदस्य |
| 4. अध्यक्ष, अपैरल निर्यात संबंधी परिषद | सदस्य |
| 5. संबंधित अभिकरण का एक अधिकारी §प्रवर्तन समिति के अध्यक्ष के परामर्श से कोट प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाना § | सदस्य सचिव |

§ 2§ क्षेत्र में अध्यक्ष और दो सदस्य हो सकते हैं ।

§ 3§ प्रवर्तन समिति ऐसे मामलों का निपटारा करेगी जिनमें निम्नलिखित में से किसी एक का भी उपयोग अन्तःप्रस्त होगा जो कि कौटुम्बिकों को प्राप्त करने, बढ़ाने, उपयोग करने अथवा उपयोग के संबंध में प्रमाण देने से संबंधित होंगे :-

§ क§ कोई भी घोषापक्षी का क्रियाकलाप

§ ख§ तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का मामला

§ ग§ ऐसे किसी भी वस्तुवैज को नकली ढंग से प्रस्तुत करना अथवा जाहिसाजी करना

§ घ§ हकदारियों को बढ़ाने के लिए ऐसे उत्तर विनियमित बैंक प्रस्तुत करना जिन्हें उसके बैंक में प्रस्तुत करने पर अस्वीकृत कर दिया जाता है ।

§ 4§ प्रवर्तन समिति ऐसे निर्यातकों से संबंधित उन मामलों का भी निपटारा करेगी जिनमें ऐसी किसी मद्द का निर्यात किया जाना पाया गया है अथवा जिसके निर्यात के लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, जिसमें सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी निर्यात मद्द में प्रयुक्त होने के लिए विशेष रूप से प्रतिबंधित कोई रंजक, रसायन, रंगद्रव्य अथवा अन्य सामग्री निहित है ।

§ 5§ ऐसे मामलों में, जिनमें समिति निर्यातक के स्पष्टीकरण की जांच करने तथा उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद निर्यातक को घोषापक्षी करने अथवा ऐसे मामलों जो उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, जैसा भी मामला हो, के लिए दोषी पाती है तो संबंधित निर्यातक को विशिष्ट अवधि के लिए पहले से प्राप्त की गई निर्यात हकदारियों का आगे प्रयोग करने उन्हें हस्तांतरित करने तथा किसी प्रकार की अन्य हकदारियों प्राप्त करने से विवर्जित किया जा सकता है ।

§ 6§ गंभीर मामलों में कौल प्रशासनिक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई से पहले प्रक्रिया के पूरा हुए बगैर तथा समिति द्वारा निर्णय को अंतिम रूप देने से पूर्व निर्यातक को अस्थायी तोर पर विवर्जित किया जा सकता है ।

§ 7§ प्रवर्तन समिति के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करने के लिए एक प्रवर्तन अपील समिति गठित की जायेगी जिसका गठन निम्नलिखित अनुसार होगा :-

1. संयुक्त सचिव निर्यात, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार अध्यक्ष
2. विधि तथा न्याय मंत्रालय, भारत सरकार सदस्य
का एक अधिकारी (जो कि उपसचिव, भारत सरकार से कम पद का न हो)
3. डी. जी. एफ. टी, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार का एक अधिकारी (जो कि उपसचिव, भारत सरकार से कम पद का न हो)
4. निदेशक/उप सचिव निर्यात, वस्त्र मंत्रालय सदस्य सचिव

§ 8§ प्रवर्तन अपील समिति के क्षेत्र में अध्यक्ष एवं इसके दो सदस्य होंगे । तथापि, प्रवर्तन अपील समिति के अध्यक्ष प्रवर्तन समिति द्वारा पारित किए गए आवेशों पर लिखित रूप से उपयुक्त कारण देते हुए स्थगन आवेश दे सकते हैं ।

§ 9§ प्रवर्तन अपील समिति के सम्मुख की जानी वाली अपील 5 प्रतिवर्षों में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को वेद्यः 500/- रु के डिमान्ड नुष्ट के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।

हस्तक्षेप

§ 10§ प्रवर्तन अपील समिति, निर्यातक से अपील प्राप्त होने पर,

प्रवर्तन समितिके आदेशों की समीक्षा, संशोधन, आलोचन अथवा स्वयं आवश्यक कार्रवाई कर सकती है ।

18. वस्त्र आयुक्त की पर्यवेक्षी भूमिका

वस्त्र आयुक्त इस नीति के क्रियान्वयन संबंधी मामलों पर सामान्य रूप से पर्यवेक्षण करेंगे । यदि इस संबंध में कोई नीतिगत अभियमितता पाई जाती है तो सुस्त उपयुक्त निदेशों के लिए वस्त्र मंत्रालय को सूचित किया जाए ।

19. समन्वय समिति

इस समिति के संचालन की समीक्षा करने के लिए समन्वय समिति की, जिसमें वस्त्र आयुक्त, निर्यात संबंधन परिषद § प. ई. पी. सी., डब्लू एच डब्लू ई. पी. सी., टेक्सफोसिल, एल. और टी. ई. पी. सी. के प्रतिनिधि और कोटा प्रशासनिक प्राधिकारी, त्वर्यकारी निदेशक, एच ई पी सी, विक्सस आयुक्त § हस्तक्षेप तथा उप सचिव/निदेशक § निर्यात§ शामिल हैं, तीन माह में एक बार संयुक्त सचिव § निर्यात§ की अध्यक्षता में बैठक होगी । यह समिति इस नीति में आवश्यक संशोधन करने के लिए अपनी रिपोर्ट वस्त्र मंत्रालय को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजेगी तथा ई. यू. को कुल प्रतिबंधित श्रेणियों में हथकरघा परिधानों के लिए अरक्षित विशेष मात्राओं के संबंध में वस्त्र समिति ऐसे उत्पादों के लिए द्विपक्षीय करारों में तथा निर्धारित प्रमाण पत्र जारी करेगी ।

20. संशोधन करने के लिए सरकार के अधिकार

सरकार के पास पूर्व सूचना दिए बिना जनीहस्त में उपयुक्त किसी भी उपबंध में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

एन. रामाकृष्णन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 1999

Subject:—Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy (2000—2004)—In respect of countries where such exports are covered by restraints under the provisions of the Agreement on Textiles and Clothing.

1. INTRODUCTION :

No. 1/128/99 Exports-I.— Pursuant to provisions contained in Item No. 8 of Appendix I, Schedule 2 of ITC (HS) classifications of Export and Import published under the Export and Import Policy (1997—2002) in respect of export of readymade garments and knitwear to the USA, Canada and the European Union, the Policy for Allotment of Entitlements (hereinafter referred to as the Allotment Policy) for the years 2000 to 2004 shall be as hereinafter detailed.

2. ADMINISTRATION:

- (i) Unless otherwise directed, the Director General, Apparel Export Promotion Council, New Delhi (DG, AEPC) shall allocate export entitlements. The DG, AEPC shall also do the necessary certification for exports of all readymade garments and knitwear covered in this Notification. DG, AEPC shall also function as 'Quota Administering Authority' as mentioned elsewhere in this Notification.
- (ii) For the purpose of this Notification, the DG, AEPC shall mean and include such other officials of the AEPC to whom the DG, AEPC expressly or otherwise delegates a part or whole of the necessary functions and responsibilities.
- (iii) The DG, AEPC, notwithstanding any delegations effected by him, shall be accountable to the Ministry of Textiles for implementation of the Allotment Policy.
- (iv) The Ministry of Textiles shall be the final authority regarding interpretation of any of the provisions of this notification. The Ministry of Textiles may also issue such guidelines as it deems fit from time to time regarding agencies of

- administration, their functions and responsibilities and may reallocate a part or whole of the functions and responsibilities to such authorities as it deems fit.
- (v) Export entitlements will be allotted only to exporters registered with the competent registering authorities as per the Export-Import Policy prevailing from time to time

3. **BASE YEAR**

The phrase “Base Year” for an allotment year, wherever appearing in this Notification, shall mean the calendar year preceding the year immediately before that allotment year. For example, for the allotment year 2000, the base year shall be 1998.

4. **SYSTEMS OF ALLOTMENT**

- (i) Quantities for export in each allotment year shall be allocated under the following systems at rates indicated against each of them:

System of Allotment	Percentage of Annual Level
Past Performance Entitlement (PPE) System	70%
(Out of which HVE)	(5%)
New Investors Entitlement (NIE) System	15%
Non Quota Entitlement (NQE) System	5%
First Come First Served (FCFS) Entitlement System	10%

- (ii) Quantities that become available from time to time on account of surrenders, flexibilities or otherwise shall also be allocated under the First Come First Served (FCFS) System.
- (iii) The Ministry of Textiles reserves the right to allocate entitlements in variation with the above, in case it is considered so desirable, in view of changes in the demand pattern and / or other relevant considerations. The Ministry may also reserve quantities for knitwear, woollen products, children's wear or any other Country/Category. Such reserved quantities will operate in the FCFS system for the products for which they have been reserved, upto 30 September and unallocated balance from the reserved quantities as on 1 October will be made available for applications in the FCFS system, without any reservations for such Countries/Categories.

5. **PAST PERFORMANCE ENTITLEMENT (PPE) SYSTEM INCLUDING THE HIGH VALUE ENTITLEMENT (HVE) SYSTEM:**

Application and Computation

- (i) The quantities earmarked for allotment in this system shall be made available on 1st January and for this purpose, applications shall be invited by the Quota Administering Authority during the previous year.

- (ii) The DG, AEPC will compute PPE.
- (iii) Available levels will be allotted pro-rata on the value of exports during the base year by the applicants in each country-category. Allotments, however, will be restricted to the average annual export performance of India in the country-category during the base year.

Computation - H.V.E.

- (iv) The average unit value realised by all exporters who have applied for PP Entitlement in a particular country-category during the base year would be worked out and exporters who have realised a higher unit value than the average unit value will be allotted additional quantities from the 5% reserved pool (HVE) on the basis of the difference between the unit value realised by an exporter and the average unit value realised in a country-category multiplied by the quantity exported by individual exporters in that country-category. The HVE of the individual exporters will be added to their PPE and will be subject to all the conditions applicable to PPE.

Allotment, Utilisation and Transferability

- (v) The allotment will be in two parts, each consisting of 50% of the allotment. The first part will be valid from the date of allotment till the 31st of May and second part will be valid till the 30th of September.
- (vi) In the case of allotment valid till the 31st of May, transfers may be allowed till the last date, but the original quota holder or the transferee shall get the certification/endorsement of shipment in respect of the entitlement by the 31st of May. Such certification/endorsement shall be valid for shipment upto the 20th of June of the quota year. Unutilised quotas (non-certified or non-shipped) shall lapse.
- (vii) In case of allotment valid till the 30th of September, transfers may be allowed till 20th September. The original quota holder or transferee may get an extension thereof till the 31st of December on payment of BG/EMD at the rates given below, subject to the condition that the extension sought is for a specific buyer. One time change of buyer can be allowed by DG, AEPC without changing other conditions applicable.

Product Group

Socks/Gloves in USA
Underwear in Canada
Group-A in Canada
Group-II in USA
Categories 4,5 & 24 in EU
Others

EMD/BG Amount

Rs.2/- per dozen pair
Rs.5/- per piece
Rs.12/- per Sq. Mtr.
Rs.12/- per SME
Rs.12/- per piece
Rs.20/- per piece

- (viii) The applications for such extension should be submitted, complete in all respects, before the expiry of the initial validity of the entitlement or within a grace period of three working days.
- (ix) The transferred PPE will be known as PPT.
- (x) Shipments against PPT shall be counted as exports by the transferee.
- (xi) Transfer of PPT is NOT allowed.

Electronic Transfer System (ETS)

- (xii) PPE transfers will be regulated by the Director General, Apparel Export Promotion Council through an Electronic Transfer Scheme with the help of an on-line computer network in which the Offers of intending transferors will be displayed in the Regional Offices of AEPC, including the quantity and Offer prices and the intending transferees will request for transfers on the basis of displayed offers. The offers and requests would be received during the working hours to be prescribed by DG, AEPC and all such offers and requests so received will be processed together. The requests will be made only against the available Offers. However, in case there is no offer on display for a particular country / category, there will be no restrictions on the quantities to be requested and the request price to be indicated.
- (xiii) DG, AEPC may take such steps as deemed necessary for facilitating the smooth and effective implementation of ETS after giving due notice to trade and after informing the Ministry of Textiles.

6. NEW INVESTORS ENTITLEMENT (NIE)

Applications and Computation

- (i) Allotments under the NIE system would be made only to exporters registered, as manufacturer-exporters and who have invested a minimum amount of Rs. 50 lakhs in new machinery either in an existing unit or in a new unit. Such machinery shall meet the eligibility criterion of the Technological Upgradation Fund Scheme currently in force.
- (ii) Allotments under this system shall be only for the export of goods manufactured in the modernised and upgraded production unit.
- (iii) The allottees shall also submit an affidavit at the time of certification of shipments that the goods being exported have been manufactured in their production units so modernised/upgraded.

- (iv) The base period for NIE will be any consecutive period of 12 months starting from the 1st January of the base year and ending with 30th June of the previous year. Thus, for the quota year 2001, any 12 constitute months from out of the 18 months period from 1.1.1999 to 30.6.2000 will constitute the base period.
- (v) Applications for NIE will be received ~~from~~ upto 30th September of the previous year by the Quota Administering Authority. An application under this system shall be accompanied by a demand draft of Rs. 500/- drawn in favour of the Quota Administering Authority and payable at New Delhi. The other terms and conditions of the application will be determined by the Textile Commissioner in consultation with the Quota Administering Authority and after seeking the prior approval of the Ministry of Textiles.
- (vi) Available quantities under the NIE will be distributed by the Quota Administering Authority on the basis of the production capacity of eligible applicants.
- (vii) Allocation to individual applicants will be distributed pro-rata among all eligible applicants on the basis of eligible investment.
- (viii) During the year 2000, NIE allocation would meet the committed liabilities under NIE pertaining to the previous years and if the liabilities are more, these would be met on a pro-rata basis but would not be carried over. The eligible persons would be required to rank their options from the available categories.

Allotment, Utilisation and Transferability

- (ix) NIE shall be allocated in two parts, each consisting of 50% of the allotment. The first part will be valid from the date of allotment till the 31st of May and second part will be valid till the 30th of September.
- (x) In case of NIE valid till 31st May, the quota holders will get the certification of shipment in respect of the entitlement by 31st May. The certification will be valid for shipment upto 20th June of the quota year. Unutilised quotas (non-certified or non-shipped) shall lapse.
- (xi) In case of NIE valid till 30th September, the quota holders can get the extension till 31st December on payment of BG/EMD at the rates mentioned in 5(vii), subject to the condition that the extension sought is for a specific buyer.
- (xii) The applications for such extension should be submitted, complete in all respects, before the expiry of the initial validity of the entitlement or within a grace period of three working days.
- (xiii) NIE shall NOT be transferable.

NON QUOTA EXPORTERS' ENTITLEMENT (NQE) SYSTEM

Application and Computation

- i) Exporters of garments to non-quota countries and non-quota garments to quota countries shall be eligible for allotment under this system provided the payment is

- received in free currency, and the exporter has a minimum export performance of Rs. 20 lacs during the base year. Exports of garments to Russia will, however, not be taken into account for NQE allotments.
- ii) The quantities earmarked for allotment in this system shall be made available on 1st January and for this purpose, applications shall be invited by the Quota Administering Authority during the previous year.
 - iii) The 'Quota Administering Authority' will compute NQE.
 - iv) Entitlements under this system will be calculated and allotted by the Quota Administering Authority on the basis of value of admissible exports during the base year. The exports of quota garments, which are covered under this Allotment Policy, to non-quota countries will, however, be given double weightage for the purpose of determining entitlements. The levels available will be distributed pro-rata on the basis of the value of exports of individual applicants.
 - v) An exporter shall be permitted a choice of ten country-category combinations for allotment

Allotment, Utilisation and Transferability

- vi) All conditions applicable to PPE shall also be applicable to NQE, *mutatis-mutandis*
- vii) NQE is transferable (such transferred entitlements hereinafter referred to as NQT) and the conditions of transfer will be the same as in the case of PPE.
- viii) All conditions applicable to PPT shall also be applicable to NQT, *mutatis-mutandis*.

8. FIRST COME FIRST SERVED (FCFS) SYSTEM:

Release Schedule

- (i) Entitlement under the FCFS System shall be opened twice in the year. 50% of the entitlement under FCFS will be released on the 10th of January and the other 50% on the 10th of April.
- (ii) In addition to the quantities under this system, those that become available by way of surrenders, flexibilities or otherwise, if any, will be released on 10th April, 10th July and 10th November. While considering any such releases, *inter-alia*, availability of quantities in different categories will also be taken into account. The quantities to be released on these dates along with the country categories and segments where the releases are made, will be announced by the Quota Administering Authority sufficiently in advance before the schedules release.
- (iii) The Ministry of Textiles may decide to release quantities in FCFS system in any dates other than the dates stipulated in (ii) above, as may be found necessary. On receipt of such a decision, the Quota Administering Authority will release such quantities in FCFS system after giving adequate notice to the trade.

Applications

- (iv) Quantities shall be allocated against applications and on a day when available quantities are oversubscribed, eligibility shall be decided on the basis of unit value realisation among the applications received on that day.

Validity of allotments

- (v) Allotments will be valid for 75 days from the date of such allotment and no extension will be granted.

System of allotment

- (vi) Allotments under the FCFS system would be subject to EMD/BG @ 5% of FOB value of the quantity involved.
- (vii) The Textile Commissioner may fix the maximum quantity that can be applied for by an applicant for each country-category under this system per day in consultation with the Quota Administering Authority.

Transferability

- (viii) FCFS allotments shall NOT be transferable.

HANDLOOM GARMENTS:

Special quantities reserved for handloom garments for certain countries would be allotted under the FCFS system

10. VALIDITY OF CERTIFICATION

- (i) Validity of certification on shipping bills in respect of FCFS allotments would be 75 days from the date of allotment unless otherwise specified.
- (ii) Validity of PPE/NIE/PPT/NQT will be 75 days from the date of endorsement of the shipping bill or till the expiry of the entitlement certificate, whichever is earlier.
- (iii) Notwithstanding anything contained in para 8(v) above, the Textile Commissioner may grant extension of validity period upto three working days in individual cases if he is satisfied that the exporter concerned could not export within the period due to circumstances beyond his control.

11. SLOW-MOVING ITEMS

- i) An item shall be notified as slow-moving, if, during the base year the utilisation has been less than 75% of the annual level for that year. The Quota Administering Authority shall notify the items that are slow moving, latest by 1st December of the previous year.
- ii) Notwithstanding anything else contained in any of the provisions of this Notification, for slow-moving items, EMD/BG would be charged @ 1% of FOB value for shipment under the FCFS system.
- iii) The quantitative ceiling stipulated for the FCFS system vide para 8(vii) above shall not be enforced
- iv) This relaxation may, however, be withdrawn at any time without any notice.

12. PROVISIONS REGARDING SUBMISSION AND FORFEITURE OF EARNEST MONEY DEPOSIT/BANK GUARANTEE/POST DATED CHEQUE**(A) SUBMISSIONS**

- (i) EMD shall ordinarily be furnished by way of Demand Draft, FDR unilaterally encashable by AEPC or Bank Guarantee. However, Legal Undertaking or Post Dated Cheques will also be accepted as EMD in systems other than FCFS, subject to the conditions stipulated below :

Legal Undertaking (LUT)

- (ii) An Export House/Trading House/Star Trading House/Super Star Trading House/Public Sector Undertaking/Manufacturer Exporter who has not been penalised by way of forfeiture order under this Allotment Policy or the previous Allotment Policy (1997-1999) and has entitlements of not less than 25,000 pieces for all country-categories taken together under the PPE, NQE and NIE systems (including PPT, NQT) may submit a Legal Undertaking (LUT) in place of EMD/BG, for extension and revalidation of the entitlements subject to the following conditions :
 - (a) If the DG, AEPC raises a claim, in terms of the Export Entitlement Distribution Policy, for any forfeiture amounts in respect of entitlements covered by a Legal Undertaking, the exporter concerned who had submitted the Legal Undertaking, would have to remit the amounts so claimed by the DG, AEPC within a period of 90 days from the date of such claim without demur or protest, failing which the exporter shall not be eligible to apply for or obtain any certification of shipping bills, transfer of Entitlements or return of EMD/BGs in any system until the amounts are remitted and the DG, AEPC decides to re0instate these facilities for the exporter.

- (b) The DG, AEPC may withdraw the facility of submitting LUT in place of EMD/BG for any exporter who is otherwise eligible for the facility, but has failed to remit any forfeiture amount within the stipulated period of 90 days.
- (c) The stipulations relating to release / forfeiture of the LUT would be the same as applicable to the other forms of EMD/BG.

Post Dated Cheques (PDC)

- (iii) Post Dated Cheques will be accepted as EMD, in systems other than FCFS, for extension of entitlements subject to the condition that if the cheque is dishonoured on deposit for any reason, the quantities extended against such cheques would be debited to any future entitlements of the concerned exporter and he will not be allotted any further entitlements until the amount covered by the forfeiture is remitted by way of Demand Draft.
- (iv) The Post Dated Cheques should be dated 1st June of the year following the year of allotment and shall be valid for presentation during a period of 6 months from that date.
- (v) The stipulations relating to release / forfeiture of the Post Dated Cheques would be the same as applicable to the other forms of EMD/BG.

(B) RELEASE/FORFEITURE

- (vi) The EMD/BG/LUT/Post Dated Cheque of an exporter who exports 90% or more of the entitlement would be released in full. However, in the case of slow moving items, this percentage will be 75% or more.
- (vii) The 'Quota Administering Authority' shall forfeit the EMD/BG, in case utilisation is 75% or more but less than 90% in case of fast moving items, and 50% or more but less than 75% in case of slow-moving items, proportionate to the shortfall in utilisation.
- (viii) If utilisation is less than the above, i.e. 75% in case of fast moving items and 50% in case of slow moving items, the EMD/BG/LUT/Post Dated Cheque shall be forfeited in full.
- (ix) For the above purpose, utilisation shall be compiled on the basis of individual entitlements or on the basis of each System separately or on the request of the exporter for his performance in all systems (except FCFS System) clubbed together.
- (x) A show cause notice shall be issued before forfeiture.
- (xi) The quota administering authority should despatch the order of forfeiture of BG/EMD/LUT/PDC etc., by registered post with acknowledgement due card or preferably through speed post. Evidence of despatch of an order through the means specified above as also of acknowledgement/receipt thereof or otherwise should be kept on the file concerned.

- (xii) The Quota Administering Authority, for ensuring the recovery of the amount of forfeiture may temporarily debar the exporter from obtaining entitlements and participating in the Export Entitlement Distribution Scheme for a specified period.

(C) PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT (PDA)

- (xiii) All forfeited EMD/BG/Post Dated Cheques shall be deposited into a Public Deposit Account of the Government in such manner as Government directs from time to time.

13. GUIDELINES FOR OBTAINING RELEASE OF HELD-UP CONSIGNMENTS

- (a) When a shipment effected in an unrestrained category is reclassified by the importing country into a restrained category or when a shipment effected in a restrained category is reclassified by the importing country into another restrained category, Export Certificates / Visas will be issued in the reclassified category after the exporter surrenders the quantity involved in the reclassified category. For this purpose, the exporter can surrender the quantity from own entitlements in systems other than FCFS or by obtaining the quantity by transfer. If the case is to be cleared after 20th September, when transfers are not permissible, and an exporter does not have own entitlements to surrender, an undertaking to surrender the requisite quantity by the 31st January from the succeeding year's entitlement (own or transferred) shall be taken from such an exporter. Such an undertaking should be backed by BG/EMD to the extent of 50% of the FOB value of the quantity. Once the quantity is surrendered, the BG/EMD may be released. If the quantity is not surrendered as per the undertaking, the BG/EMD may be forfeited. In such cases, PPE allotments in any country-category to the exporter for the succeeding year may be allotted, only after the requisite quantity is so surrendered.
- (b) If unallocated balance is available in the reclassified categories from the quantities released by the Quota Administering Authority in FCFS system, the Export Certificate / visas for the held up consignment will be issued after debiting such balance and the exporter will not be required to surrender any quantity.
- (c) The stipulations of (a) and (b) above will also apply to cases where a change of buyer is required for a shipment that had been effected under the FCFS system or under the PPE system after obtaining extension beyond 30th September and to cases where a change of importing country is required.
- (d) Where a shipment exported in a restrained category reclassified into another restrained category as above, the entitlement used for sending the shipment from the country may be returned to the exporter, subject to the following conditions

- (i) The exporter returns the Original Export Certificate / Visa to the Quota Administering Authority.
- (ii) The Entitlement Certificate which had been debited at the time of export, remains valid for the concerned quantity when the add-back is requested.
- (e) In the case of items exported as handloom garments exempted from restraints or as "India Items", which are reclassified by the importing countries as restrained items, Visas/Export Certificates will be issued by the Quota Administering Authority after obtaining the approval of the Ministry of Textiles.

14. CLEARANCE BY CUSTOMS:

(A) PRODUCTION UNDER RESTRAINT INCLUDING ITEMS NOT SUBJECT TO SPECIFIC LIMITS IN THE USA

Shipments will be allowed by the Customs Authorities at the port of shipments after verifying the certification of export entitlement in the original and duplicate of shipping bills for individual consignments, issued by the DG, AEPC.

(B) HANDLOOM GARMENTS

For export of all handloom garments, corresponding to restrained items in Canada and special quantities reserved for handloom garments in some of the restrained categories relating to the USA, Shipments will be permitted by the Customs on the basis of an Inspection Endorsement by the Textiles Committee in part 2 of the combination form.

(C) GARMENTS FALLING UNDER "INDIA ITEMS" :

In respect of 'India item' which are traditional folklore handcraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for exports to the EU, the USA and Canada on the basis of an appropriate certificate issued by the office of the Development Commissioner (Handicrafts).

15. EXPORT CERTIFICATES ETC.

Export Certificate, Certificate of Origin and Visa

The following certificates required under the relevant Bilateral Textile Agreements will be issued by the DG, AEPC:-

- (i) EU
 - (a) Export Certificates and Certificates of Origin for all garment/knitwear items under restraint.
 - (b) Certificates of Origin for all non-restrained garments/knitwear items.

- | | | |
|-------|--------|---|
| (ii) | Canada | Export Certificates for garments that are subject to restraint except for properly marked samples valued at Canadian \$ 500 or less |
| (iii) | U.S.A. | Visa for all garment/knitwear consignments except properly marked samples valued at US \$ 800 or less. |

Handloom Certificate

In the case of export of all Handloom Garments, corresponding to restrained items to Canada and all Handloom Garments corresponding to the restrained categories to the EU, the Textiles Committee will issue the certificate as prescribed in the Bilateral Agreements for such products.

16. APPEAL AGAINST FORFEITURE OF EMD/BG/POST DATED CHEQUE

- i) Any exporter aggrieved by the order of forfeiture of EMD/BG by the quota administering authority may file an appeal to the 1st appellate authority, i.e., the Textile Commissioner within 45 days of the despatch of the order of the quota administering authority. This appeal shall be made in triplicate, accompanied by a demand draft for Rs. 500/-, drawn in favour of the Textile Commissioner and payable at Mumbai.
- ii) The appellant may make a separate application for stay of the order of the quota administering authority.
- iii) The Textile Commissioner shall decide the issue of stay, as early as possible.
- iv) A decision on the appeal shall also be taken as early as possible, preferably within two months. A reasonable opportunity for personal hearing, if requested by the appellant, shall be given. The final order will be despatched through registered post (with acknowledge due card) or preferably through speed post and the evidence of despatch thereof by the said means, as also of acknowledgement/receipt thereof or otherwise will be placed on the file concerned.
- v) In the case of appeals which have been filed after the due date, the Textile Commissioner shall first decide as to whether such delay is to be condoned or not. The Textile Commissioner shall pass a speaking order in such cases expeditiously.
- vi) For the above purposes, the Textile Commissioner shall mean and include such other officer (not below the rank of Director) to whom the Textile Commissioner, expressly or otherwise delegates the necessary responsibilities.
- vii) An exporter who is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner in the matter of a stay application or an appeal, may prefer an appeal against such decision within 45 days of the despatch of the order of the 1st appellate authority to the 2nd appellate authority for a decision thereon.
- viii) The 2nd appellate committee for these purposes will comprise of the following:

(a) Joint Secretary (Exports), MOT, GOI	Chairman
(b) An officer of the Ministry of Law & Justice, GOI	Member

- (not below the rank of Dy. Secy. to the GOI)
- (c) An officer of the DGFT, MOC, GOI Member
(Not below the rank of Dy. Secy. to the GOI)
- (d) Dy. Secretary/Director (Exports), MOT, GOI Member-Secretary
- The quorum of the this committee will consist of its Chairman and 2 members.
- ix) Any appeal before the 2nd appellate authority shall be addressed to its Member-Secretary in a set of five copies and shall be accompanied by a demand draft for Rs. 500/-, drawn in favour of the Ministry of Textiles, GOI and payable at Delhi
- x) If matter of the appeal also pertains to a stay and is of an urgent nature, the Chairman of the committee may grant the stay by recording reason(s) in writing expeditiously.
- xi) The 2nd appellate authority shall also decide the case at the earliest, preferably within three months.

17. PROCEDURE TO DEAL WITH QUOTA MALPRACTICES BY EXPORTERS

- i) A Committee called the Enforcement Committee is constituted with the following composition:-
- | | |
|--|------------------|
| 1) Textile Commissioner, MOT, GOI | Chairman |
| 2) DG, AEPC | Member |
| 3) An officer of the Ministry of Law & Justice, GOI
(not below the rank of Dy. Secy. to the GOI) | Member |
| 4) Chairman AEPC | Member |
| 5) An Officer of the Agency concerned
(To be nominated by Quota Administering
Authority in consultation with the Chairman
of the Enforcement Committee) | Member-Secretary |
- (ii) The Chairman and two members will constitute the quorum.
- (iii) The Enforcement Committee will deal with cases involving the use of any one of the following, in connection with obtaining, extending, utilising or proving the utilisation of quotas:-
- a) Any fraudulent activity
 - b) Any misrepresentation of facts
 - c) Any falsification of documents or forgery
 - d) Submission of post-dated cheques for extension of entitlements which are dishonoured on presentation to his bank.
- (iv) The Enforcement Committee will also deal with cases relating to exporters who are found to have exported or who have completed the formalities to export any item, which contains any dyes, chemicals, pigments or other material whose handling is specifically banned by the competent authority of the Government.

- (v) In cases where the Committee finds the exporters guilty of fraud or other irregularities, which are violative of any of the above provisions, after examining his explanation and giving a personal hearing, the exporter may be debarred from obtaining entitlements and participating in the Export Entitlement Distribution Scheme for a specified period.
- (vi) In serious cases, the exporter may be temporarily debarred by the Quota Administering Authority before personal hearing, pending the completion of the procedures and finalisation of a decision by the Committee.
- (vii) The Enforcement Appellate Committee with the following composition will hear appeals against the decision of the Enforcement Committee:

i)	Joint Secretary (Exports), MOT, GOI	Chairman
ii)	An officer of the Ministry of Law & Justice, GOI (Not below the rank of Dy. Secretary to the GOI)	Member
iii)	An officer of the O/o the DGFT, MOC, GOI (Not below the rank of Dy. Secretary to the GOI)	Member
iv)	Dy. Secretary/Director (Exports), MOT, GOI	Member-Secretary.
- (viii) The quorum of the Enforcement Appellate Committee will consist of the Chairman and 2 members. The Chairman of the Enforcement Appellate Committee will, however, have the power to grant stay on the orders passed by the Enforcement Committee, after giving reasons recorded in writing.
- (ix) Any appeal filed before the Enforcement Appellate Committee shall be presented in five sets of papers accompanied by a demand draft for Rs. 500/-, drawn in the favour of the Ministry of Textiles, GOI.
- (x) The Enforcement Appellate Committee may review and amend, modify or quash the orders of the Enforcement Committees on appeal from an aggrieved exporter or by initiating the action suo-moto.

18. SUPERVISORY ROLE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

The Textile Commissioner shall exercise general supervision over the matters relating to implementation of this Policy. In case, any deviation is noticed by the Textile Commissioner, it shall be promptly reported to the Ministry of Textiles seeking directions thereon.

19. COORDINATION COMMITTEE

A Coordination Committee consisting of Textile Commissioner, the representatives of EPCs (AEPC, TEXPROCIL SRTEPC and WVEPC) including the Quota Administering Authorities, ED, HEPC, DC(HC) and Dy. Secretary/Director (Exports) will meet under the chairmanship of the Joint Secretary (Exports) once in three months to review the operation of the policy. The Committee will send a report to the Ministry for taking appropriate actions on any changes desired in the Policy.

20. RIGHT OF THE GOVERNMENT TO MAKE AMMENDMENT

Government reserves the right to make amendments to and of the foregoing provisions in the public interest, without giving prior notice.

N RAMAKRISHNAN, Jt. Secy.